प्रेस विज्ञप्ति

विषय: यूनियन बजट’ 2026 पर सेमीनार संपन्न

कानपुर 7 फरवरी 2026। उन्नीसवीं सदी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था का स्वरूप पूंजी आधारित हो गया, जिसके परिणामस्वरूप पूंजीवाद और मार्क्सवाद जैसी विचारधाराएँ उभरीं, परंतु इक्कीसवीं सदी में यह स्पष्ट हो चुका है कि प्राकृतिक और पूंजीगत संसाधनों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण संसाधन मानव संसाधन है। उपरोक्त विचार सी.ए. (डॉ.) डी. आर. अग्रवाल ने मर्चेंट चैम्बर ऑफ़ उत्तर प्रदेश, कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन एवं कानपुर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित बजट एवं आर्थिक विमर्श कार्यक्रम में देश की वर्तमान आर्थिक संरचना, वैश्विक परिदृश्य तथा भारत की दीर्घकालीन विकास चुनौतियों पर रखे।

उन्होंने कहा कि आई.पी.सी.सी. की रिपोर्टों का उल्लेख करते हुए कहा कि औद्योगीकरण के बाद प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से वैश्विक तापवृद्धि जैसी समस्याएँ सामने आईं। बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध और इक्कीसवीं सदी में विज्ञान, तकनीक, नवाचार और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का उदय हुआ है, जहाँ मानव मस्तिष्क ही सबसे बड़ा पूंजीगत संसाधन बन चुका है। उन्होंने बताया कि आज शीर्ष वैश्विक कंपनियाँ मशीन या सामग्री आधारित नहीं, बल्कि ज्ञान, तकनीक और इनोवेशन आधारित हैं, जैसे गूगल, एप्पल, फेसबुक आदि, जो इस परिवर्तन का प्रत्यक्ष उदाहरण हैं।

भारत की स्थिति पर चर्चा करते हुए वक्ता ने कहा कि विश्व की लगभग 18–19 प्रतिशत जनसंख्या होने के बावजूद भारत की वैश्विक आय में हिस्सेदारी 5 प्रतिशत से भी कम है, जबकि चीन और अमेरिका ने अपनी जनसंख्या के अनुपात में आय और तकनीकी क्षमता का संतुलन साध लिया है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि भारत की विशाल युवा जनसंख्या होने के बावजूद मानव संसाधन का आर्थिक दोहन अपेक्षित स्तर तक नहीं हो पा रहा है।

वक्ता ने यह भी बताया कि भारत का वर्तमान आर्थिक संतुलन मुख्यत: सेवा क्षेत्र, विशेषकर आईटी सेवाओं और प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजे गए धन पर निर्भर है। व्यापार घाटे की भरपाई के लिए देश विदेशी पूंजी, एफडीआई, एफपीआई और विदेशी ऋण पर निर्भर होता जा रहा है, जिससे विदेशी पूंजी का भार बढ़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विदेशी पूंजी से बना विदेशी मुद्रा भंडार वास्तविक अर्थों में रिज़र्व नहीं, बल्कि एक दायित्व है।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कमजोर प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि भारत आज भी गुणवत्ता, लागत और तकनीकी दक्षता के स्तर पर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं जैसे क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व इस कमजोरी को उजागर करता है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकों के आगमन से भविष्य में सेवा क्षेत्र का वर्तमान अधिशेष भी चुनौती में पड़ सकता है।

कार्यक्रम में यह भी रेखांकित किया गया कि भारत में अनुसंधान एवं विकास पर जीडीपी का मात्र 0.7 प्रतिशत खर्च होता है, जबकि अमेरिका, चीन और जर्मनी जैसे देश 2.5 से 3 प्रतिशत तक निवेश करते हैं। पेटेंट फाइलिंग के आंकड़े भी भारत की कमजोर इनोवेशन संस्कृति को दर्शाते हैं। वक्ता ने कहा कि बिना मजबूत रिसर्च और डेवलपमेंट के न तो आर्थिक वृद्धि संभव है, न रोजगार सृजन, और न ही गरीबी व आय-असमानता का समाधान।

अंत में मुख्य वक्ता ने जोर देकर कहा कि भारत को आत्मनिर्भर और टिकाऊ आर्थिक शक्ति बनने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता, कौशल विकास, अनुसंधान, स्टार्ट-अप्स, इनक्यूबेशन सेंटर और नवाचार आधारित इकोसिस्टम पर गंभीरता से निवेश करना होगा। तकनीक आयात करने के बजाय तकनीक निर्माण की दिशा में बढ़ना ही दीर्घकालीन समाधान है।

कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एड. प्रदीप कुमार द्विवेदी ने कहा कि बजट 2026-27 को संक्षेप में कहा जाए तो यह राहत घोषणाओं का नहीं, बल्कि विश्वास, व्यवस्था-सुधार और दीर्घकालिक स्थिरता का बजट है, जिसमें सरकार की गवर्नेंस फिलोसफी में स्पष्ट बदलाव दिखता है। इस बजट में ट्रस्ट-बेस्ड गवर्नेंस के तहत सेल्फ-डिक्लेरेशन, ऑटोमेशन और रिस्क-बेस्ड जाँच पर ज़ोर देकर करदाता को संदेह की दृष्टि से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास के सहभागी के रूप में देखा गया है। राज्यों को बड़े पैमाने पर संसाधन हस्तांतरण से सहकारी संघवाद को वास्तविक मजबूती मिली है, वहीं एम्.एस.एम्.ई., स्वरोज़गार और सेवा क्षेत्र को संरचनात्मक रूप से सशक्त करने की नीति अपनाई गई है। पूंजीगत व्यय और अवसंरचना में निरंतरता यह संकेत देती है कि सरकार अल्पकालिक लोकलुभावनता के बजाय दीर्घकालिक उत्पादक परिसंपत्तियों पर निवेश कर रही है। ऊर्जा सुरक्षा, हरित संक्रमण, कौशल विकास और युवाओं के लिए अवसर सृजन पर संतुलित दृष्टिकोण के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन का एक विश्वसनीय रोडमैप प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह बजट तात्कालिक वाहवाही के बजाय भविष्य की मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था की नींव रखने वाला प्रतीत होता है।

कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सदस्यों ने इस विचारोत्तेजक वक्तव्य को भविष्य की नीति-दिशा तय करने वाला बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मर्चेंट चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष अतुल कनोडिया, सभापतित्व फिस्कल कमेटी के कन्वेनर सी.ए. अनिल के. सक्सेना, सञ्चालन सी.ए. सुधीन्द्र जैन एवं धन्यवाद सी.ए. अखिलेश तिवारी ने दिया।

कायर्क्रम में प्रमुख रूप से सर्वश्री

अनिल अग्रवाल, सी.ए. संजय शुक्ला, शरद सिंघल, नितिन ओमर, मनीष श्रीवास्तव, दीप कुमार मिश्र, मनु अग्रवाल, महेंद्र नाथ, शरद शेखर श्रीवास्तव, राजीव कुमार गुप्ता, आशीष जौहरी, विमल बाजपेई, अंशुल श्रीवास्तव, अवधेश मिश्र, अतुल मेहरोत्रा, शैलेश शर्मा, केशव बाजपेई, सिद्धार्थ अग्रवाल आदि उपस्थित थे।